



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]
No. 123]नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

फा. सं. 23/2/2005-आर एण्ड आर (खण्ड IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ नीति अधिसूचित करने संबंधी भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I खण्ड I में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/2/2005-आर एण्ड आर (खण्ड III) दिनांक 6 जनवरी 2006 में निम्न संशोधन किए जाते हैं।

टैरिफ नीति के पैरा 5.1 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया है:

"बशर्ते कि जल विद्युत परियोजना जो कि राज्य के नियंत्रण/स्वामित्व वाली कंपनी न हो, के विकासकर्ता को सेवा विनियमों की कार्यनिष्ठादन आधारित लागत के आधार पर उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित कराने का विकल्प होगा यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है

(क) उपयुक्त आयोग संतुष्ट है कि एक पारदर्शी द्वि-स्तरीय प्रक्रिया अपनाने के पश्चात संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ता को परियोजना स्थल आवंटित किया गया है। प्रक्रिया का प्रथम स्तर पूर्व अहर्ता हेतु निम्न मानदण्डों के आधार पर होना चाहिए जैसे कि निवल मूल्य द्वारा मापी गई वित्तीय क्षमता, समान आकार की अवसंरचात्मक परियोजनाओं को विकसित करने का विगत अनुभव टर्न-ओवर कार्यनिष्ठादन गारन्टी को पूरा करने की योग्यता इत्यादि। दूसरे स्तर पर केवल एक सकल मात्रानिर्धारक पैरामीटर यथा 13% से अधिक निःशुल्क विद्युत, राज्य सरकार को प्रदान की गई इक्विटी भागीदारी अथवा अग्रिम भुगतान इत्यादि के आधार पर बोलियां आमंत्रित की जाए।

(ख) 100 मे.वा. डिजाइन क्षमता से अधिक की परियोजनाओं, जिनके लिए स्थलों का आवंटन एक पारदर्शी मानदण्ड प्रक्रिया अपनाकर और पूर्व निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की गई है, को भी इस

(ग) के.वि.प्रा. की स्वीकृति (यदि अधिनियम की धारा 8 के तहत अपेक्षित हो) वित्तीय समापन, कार्य सौंपना, वितरण लाइसेंस धारियों के साथ नीचे (घ) में निर्धारित क्षमता का दीर्घकालीन पीपीए (35 वर्षों से अधिक) 31.12.2010 तक पूरे कर लिए जाएं।

(घ) दीर्घावधि पीपीए कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा का कम से कम 60% होगा। किंतु 60% तक के इस आंकड़े में निर्माण के आरंभ होने से पूर्व उपर्युक्त आयोग द्वारा अनुमोदित निर्धारित तारीख की तुलना में परियोजना की अंतिम यूनिट के शुरू होने से प्रत्येक 6 माह के विलंब के लिए 5% तक की वृद्धि होगी। परियोजना के सभी यूनिटों को शुरू करने के लिए समयावधि उपयुक्त आयोग द्वारा आरंभिक सूची के अनुमोदन की तारीख से 4 वर्ष होगी। किंतु, उपयुक्त आयोग, कारणों को लेखाबद्ध करने के पश्चात् बड़ी स्टोरेज परियोजनाओं तथा 500 मेगावाट क्षमता से अधिक की रन-ऑफ-दि-रिवर परियोजनाओं के लिए लंबी समयावधि निर्धारित कर सकेगा। चालू करने के निर्धारित समय की प्राप्ति हेतु सहमत समय-सीमाओं के अनुसरण की जांच स्वतंत्र तृतीय पक्ष जांच के माध्यम से की जाएगी।

(ड.) उपकरण की आपूर्ति एवं परियोजना के निर्माण के लिए ठेका सौंपने का कार्य, या तो टर्न-की के माध्यम से अथवा सुप्रभावित पैकेजों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर किया जाता है।

उन मामलों में, जहां उपरोक्त (क) से (ड.) में वर्णित शर्तें पूरी की जाती हैं, उपयुक्त आयोग निम्नलिखित को सुनिश्चित करते हुए टैरिफ निर्धारित करेगा:-

(i) परियोजना स्थल आबंटित करने (13% तक की निःशुल्क विद्युत के अलावा) के लिए परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किए गए अथवा वहन किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय न तो परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा और न ही इस प्रकार का कोई व्यय की टैरिफ में शामिल किया जाएगा।

(ii) परियोजना लागत में निम्नलिखित शामिल होगा-

➤ परियोजना की अनुमोदित आर एंड आर योजना की लागत निम्नलिखित के अनुसार होगी:

- (क) वर्तमान में मान्य राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति
- (ख) आर एंड आर पैकेज जैसा कि परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

➤ विद्युत मंत्रालय मंजूर की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में आरजीजीवीवाई परियोजना के लिए परियोजना विकासकर्ताओं के 10% योगदान की लागत।

(iii) वार्षिक निर्धारित प्रभाव कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा के संबंध में दीर्घावधि पीपीए के आधार पर टाई-अप की गई विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा के लिए आनुपातिक रूप से ली जाएगी जिसे कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा से निम्नलिखित को घटाकर प्राप्त किया जाएगा-

(क) 13% निःशुल्क विद्युत (मेजबान सरकार के लिए 12% तथा राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के योगदान के लिए 1%)। इस 12% निःशुल्क विद्युत को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पथक-पथक समय के लिए रखा जाए।

(ख) आरंभन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए नामोदिष्ट पुनर्स्थापन क्षेत्र/परियोजना क्षेत्रों में संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली के बराबर ऊर्जा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।"

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुभोदित आर एंड आर प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं

1. समावेशन सीमा

जल विद्युत परियोजना के विकास से एक भी परिवार के प्रभावित होने पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल होंगे।

2. परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) की परिमाण

परियोजना प्रभावित परिवार वह है जिसका निवास-स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्रोत जल विद्युत परियोजना के कार्य से प्रभावित हुआ हो और जो एल ए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो। प्रभावित परिवार में स्क्वॉटर (अनधिकृत निवासी) भी शामिल होंगे।

3. कृषिक श्रमिक की परिमाण

ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र के घोषित होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और मुख्यतः कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के जरिए आजीविका चलाता हो।

4. गैस-कृषिक श्रमिकों की परिमाण

ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र के घोषित होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और उसका प्रभावित क्षेत्र में कोई जमीन न हो और वह अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम से या ग्रामीण शिल्पकार या समुदाय सेवा प्रदाता के रूप में चलाता हो।

5. स्क्वॉटर (अनधिकृत निवासी) की परिमाण

प्रभावित क्षेत्र में कानूनी अधिकार रहित सरकारी भूमि का कब्जादार परिवार और वह एल ए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्ष पूर्व से वहां रह रहा

6. पुनर्वास/पुनःस्थापन कॉलोनियाँ

इस नीति का उद्देश्य उन परियोजना प्रभावित परिवारों का बना-बनाया मकान उपलब्ध कराना है जो हाइड्रो परियोजनाओं के विकास के कारण विस्थापित हो गए हों। किन्तु इच्छानुसार इसके बदले उदार मकान निर्माता भत्ता भी दिया जाएगा।

7. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों तथा स्थानीय लोगों को सतत आजीविका के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देता है। निर्माण शुरू होने से कम से कम छह महीने पूर्व परियोजना विकासकर्त्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए आई टी आई द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे पीएफ एवं परियोजना के आस-पास में रह रहे लोगों की रोजगारोपयोगिता में वृद्धि होने की आशा है।

8. अतिरिक्त प्रावधान

इन नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान भी हैं:

- मेघावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- विकत्सा सुविधाओं का विस्तार
- विवाह अनुदान
- जीवन-निर्वाह अनुदान
- सहकारियों एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आय उत्पादन योजनाओं हेतु सहायता
- बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक सब्सिडी तथा सिंचाई सहायता

उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधानों के अलावा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पर राष्ट्रीय नीति के विद्यमान में लागू प्रावधान सामान्यतः प्रभावी बने रहेंगे।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 31st March, 2008

F. No. 23/2/2005-R&R (Vol. IV).—In this Ministry's Resolution F. No. 23/2/2005-R&R(Vol.III) dated 6th January, 2006 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, notifying the Tariff Policy under the provisions of Section 3 of the Electricity Act 2003, the following amendment is hereby made:

The following proviso is added at the end of Para 5.1 of the Tariff Policy:

“Provided that a developer, of a hydroelectric project, not being a State controlled/ owned company, would have the option of getting the tariff determined

- a) The appropriate Commission is satisfied that the project site has been allotted to the developer by the concerned State Government after following a transparent two stage process. The first stage should be for prequalification on the basis of criteria such as financial strength as measured by networth, past experience of developing infrastructure projects of similar size, past track record of developing projects on time and within estimated costs, turnover and ability to meet performance guarantee etc. In the second stage, bids are to be called on the basis of only one single quantifiable parameter, such as, free power in excess of 13%, equity participation offered to the State Government, or upfront payment etc.
- b) Projects of more than 100 MW design capacity for which sites have been awarded earlier by following a transparent process and on the basis of predetermined set of criteria would also be covered in this dispensation.
- c) Concurrence of CEA (if required under section 8 of the Act), financial closure, award of work and long term PPA (of more than 35 years) of the capacity specified in (d) below with distribution licensees are completed by 31.12.2010.
- d) Long term PPA would be at least for 60% of the total saleable design energy. However, this figure of 60% would get enhanced by 5% for delay of every six months in commissioning of the last unit of the project against the scheduled date approved by the Appropriate Commission before commencement of the construction. The time period for commissioning of all the units of the project shall be four years from the date of approval of the commissioning schedule by the Appropriate Commission. However, the Appropriate Commission may, after recording reasons in writing, fix longer time period for large storage projects and run-off-the river projects of more than 500 MW capacity. Adherence to the agreed timelines to achieve the fixed commissioning schedule shall be verified through independent third party verification.
- e) Award of contracts for supply of equipment and construction of the project, either through a turnkey or through well defined packages, are done on the basis of international competitive bidding.

In cases, where the conditions mentioned above at (a) to (e) are fulfilled, the Appropriate Commission shall determine tariff ensuring the following :

- (i) Any expenditure incurred or committed to be incurred by the project developer for getting project site allotted (except free power upto 13%) would neither be included in the project cost, nor any such expenditure shall be passed through tariff.
- (ii) The project cost shall include the
- cost of the approved R&R plan of the Project which shall be in conformity with the following :
 - (a) the National Rehabilitation & Resettlement Policy currently in force;

- (b) the R&R package as enclosed at appendix;
 - and
 - the cost of project developers' 10% contribution towards RGGVY project in the affected area as per the project report sanctioned by the Ministry of Power.
- (iii) Annual fixed charges shall be taken pro-rata to the saleable design energy tied up on the basis of long term PPAs with respect to total saleable design energy. The total saleable design energy shall be arrived at by deducting the following from the design energy at the bus bar:
- a) 13% of free power (12% for the host Government and 1% for contribution towards Local Area Development Fund as constituted by the State Government). This 12% free power may be suitably staggered as decided by the State Government
 - b) Energy corresponding to 100 units of electricity to be provided free of cost every month to every Project Affected Family notified by the State Government to be offered through the concerned distribution licensee in the designated resettlement area/ projects area for a period of ten years from the date of commissioning.”

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

APPENDIX

SALIENT FEATURES OF THE APPROVED R&R PROVISIONS FOR HYDRO POWER PROJECTS.

1. SCOPE OF COVERAGE

The following provisions shall be applicable even if one family is affected by the development of a Hydro Power Project.

2. DEFINITION OF PROJECT AFFECTED FAMILIES (PAFs)

A Project Affected Family (PAF) shall mean a family whose place of residence or other property, or source of livelihood has been affected by the development of a hydro project and who have been residing in the affected zone for two years preceding the date of declaration of notification under Section-4 of LA Act. The affected family would also include **squatters**.

3. DEFINITION OF AGRICULTURAL LABOURER

A person normally residing in the affected zone for two years preceding the date of declaration of the affected zone and earns his / her livelihood principally by manual labour on agricultural land.

4. DEFINITION OF NON AGRICULTURAL LABOURER

A person normally residing in the affected zone for two years preceding the date of declaration of the affected zone and who does not hold any land in the affected zone but earns his / her livelihood principally by manual labour or as rural artisan or a service provider to the community.

5. DEFINITION OF SQUATTERS

A family occupying government land in the affected zone without a legal title, at least for 5 years prior to the date of declaration of notification under Section -4 of L.A. Act.

6. REHABILITATION / RESETTLEMENT COLONIES

This policy aims to provide built up houses to Project Affected Families (PAFs) who get displaced due to the development of hydro projects to the extent possible. However, wherever opted for, liberal House Construction Allowance would be given in lieu.

7. TRAINING AND CAPACITY BUILDING

This policy also emphasizes the need to provide training to the Project Affected Families as well as to the local population for a sustained livelihood. Special training programmes from ITIs aimed at providing the required skills to the local population would be undertaken by the Project developers at least six months prior to commencement of construction. This is expected to boost the employability of the PAFs and other people residing in the vicinity of the project.

8. ADDITIONAL PROVISIONS

This policy envisages additional provisions for Project Affected Families such as:

- scholarships for meritorious students,
- extension of medical facilities,
- marriage grants,
- subsistence grants,
- support for income generation schemes for cooperatives and self help groups,
- seed, pesticides and fertilizer subsidies, and irrigation support.

Besides the additional provisions mentioned above, the normally applicable provisions of the National Policy on Rehabilitation and resettlement, currently in force, would be applicable